एच.एल.दुसाध डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया

डॉ. कौलेश्वर 'प्रियदर्शी'
डॉ. अनीता गौतम

एच.एल. दुसाध
डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया

संपादक

डॉ. कौलेश्वर प्रियदर्शी–डॉ. अनीता गौतम

पब्लिकेशन्स
अतुल्य

प्रकाशक : **अतुल्य पब्लिकेशन्स**
सी-5/एफ-2, ईस्ट ज्योति नगर
दिल्ली-110093
computekin@gmail.com

© सर्वाधिकार : लेखक

प्रथम संस्करण : 2017

द्वितीय संस्करण : 15 मार्च, 2020

आईएसबीएन : 978-93-82553-19-9

मूल्य : 100/- रुपये

शब्द-संयोजन : कम्प्यूटेक सिस्टम, दिल्ली-110032

मुद्रक : कॉम्पैक्ट प्रिंटर्स, दिल्ली-110032

अनुक्रम

सम्पादकीय 5

हम सबसे भयावह दौर में हैं–साल में दो करोड़ नौकरियां देने की जगह, अब नौकरी पैदा करने की नसीहत–5, टॉप की दस प्रतिशत आबादी के पास 81 प्रतिशत धन-संपत्ति–6, दुसाध के व्यक्तित्व और कृतित्व को सामने लाने की क्यों पड़ी जरुरत!–7, यह आरक्षण पर संघर्ष का परिणाम है–7, भारत का इतिहास : आरक्षण पर केन्द्रित संघर्ष का इतिहास–8, आरक्षण पर संघर्ष के आधुनिक नायक–8, मंडलोत्तर भारत में ही जुटा हिन्दू साम्राज्यवाद के ध्वंस का सामान–9, आरक्षण का वर्गीकरण : बहुजन एकता पर शासक दलों का बड़ा हमला–10, इतिहास के गर्भ से निकला डाइवर्सिटी का मुद्दा–11, आर्थिक विषमता के खात्मे के लिए ही वजूद में आया : बीडीएम–13, मानव जाति की बड़ी समस्याएं : विविधता की अनदेखी का परिणाम–13, मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या पर : दुसाध का अनोखा चिंतन–14, बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का उदय–15, डाइवर्सिटी लागू करवाने के लिए : फ्रांस क्रांति का रूप देना होगा–17, बहुजन मूव्हमेंट को गति देने में 50% योगदान अकेले दुसाध का–18, राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में डाइवर्सिटी–19, डाइवर्सिटी टाइप मुद्दे के समक्ष भाजपा की हार–20, वर्तमान हालात में दुसाध का चिंतन और प्रासंगिक क्यों!–20, भाजपा को शिकस्त देना पहले से कठिन!–22, सावधान! मोदी को सामाजिक न्याय का नया मसीहा बनाने कि तैयारी चल रही है–22, भाजपा की शक्ति के स्रोत–26, बहुजनवादी दलों की शक्ति का स्रोत : सामाजिक अन्याय का शिकार विशालतम आबादी–27, बहुजनों की सापेक्षिक वंचना : भाजपा के खिलाफ साबित हो सकती है बारूद का ढेर!–28, सापेक्षिक वंचना के सद्व्यवहार के लिए : डाइवर्सिटी–30

अध्याय-1 : परिचय : दुसाध और डाइवर्सिटी 35

एच.एल.दुसाध की पुस्तकें 36

मानव-जाति की बड़ी समस्याएं : विविधता की अनदेखी का परिणाम–एच.एल. दुसाध 41

अध्याय-2 : दुसाध की पुस्तकों पर विद्वानों की राय–डॉ. अनीता गौतम 62

क्रांतिकारी समाज वैज्ञानिक रचना–62, एक बहुविषयक और बहुआयामी ग्रन्थ–63, दलित चेतना के इतिहास में एक मील का पत्थर–64, दुसाध जी को ज्ञानपीठ और

नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए–65, राष्ट्रीय अखबारों में पहला लेख : ओलम्पिक और हम–66, अछूत की कसौटी सछूत के लिए–अभय कुमार दुबे–66, दुसाध : हिन्दू पत्रकारिता के लिए एक बड़ी चुनौती–68, डाइवर्सिटी पर केन्द्रित भारत की पहली किताब–69, दलित आन्दोलनकारियों के लिए धारदार हथियार–70, विस्मित हुए पाठक–70, भूमंडलीकरण की अर्थनीति की मुकम्मल काट–71, हिंदुत्व की राजनीति पर विशालतम रचना : सामाजिक परिवर्तन में बाधक : हिंदुत्व–71, हिंदी पत्रकारिता में एक नया अध्याय–72, सामाजिक परिवर्तन और बीएसपी–73, दुसाध का ओरिजिनल आंकलन–74, दुसाध : अत्यंत उच्चकोटि के थियोरेटीशियन–74 सवर्ण लेखकों से भिन्न आंकलन–74, बसपा को भारतीय संरचनात्मक परिवर्तन के एक कारक के रूप में, हिंदी में किसी लेखक ने ऐसा अध्ययन नहीं किया–75, दुसाध पत्रकार या किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर!–75, दलित और बहुजनों से जुड़ी पत्रकारिता के साम्राज्य पर दुसाध का एकछत्र राज–76

अध्याय-3 : एच.एल. दुसाध : फेसबुक पर सक्रिय विद्वानों की नजर में **78**

Brijpal Bharti–80,Kanwal Bharti–80, Dr. Lal Ratnakar–80, Sobran Kabir–81, Shailendra Mani–81, Satish Chandra Gaurav–82, देशदीपक दुसाध–82, Mukesh Kumar Kumar–82, Lalajee Nirmal–83, Karmendu Shishir–83, Arvind Kumar Chakrawarti–83, Frank Huzur–83, Adv. Arun Prakash–84, Chandra Bhushan Singh Yadav–84

अध्याय-4 : विद्वानों की नजर में : दुसाध का चिंतन

आरक्षण पर एक नया प्रस्ताव–दिलीप मंडल 84

बहुजनों में बहुजनों का विकास कैसे हो!–सुधीन्द्र कुलकर्णी 89

एच. एल. दुसाध : डाइवर्सिटी मैन ऑफ इण्डिया–अभिजीत कुमार 93

एच.एल. दुसाध : समकालीन भारत के कार्ल मार्क्स–डॉ. राजबहादुर मौर्य 96

धन-धरती : डाइवर्सिटी केन्द्रित पहला उपन्यास–सुरेश पंडित 107

डाइवर्सिटी, बीडीएम और दुसाध–डॉ. कौलेश्वर प्रियदर्शी 113

डाइवर्सिटी : आंबेडकरी आन्दोलन का पर्याय–113, डाइवर्सिटी के योद्धा–113, आरक्षण की सीमाबद्धता–114, डाइवर्सिटी की व्यापकता–115, डाइवर्सिटी के सूत्रपात्री : चंद्रभान प्रसाद–116, एच.एल. दुसाध ने डाइवर्सिटी को दिया जन-आंदोलन का रूप–117, बीडीएम बनाम कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र–117, डाइवर्सिटी आन्दोलन का असर–118

एच.एल. दुसाध : हिन्दी पत्रकारिता में एक नया अध्याय जोड़ने वाला दलित पत्रकार–प्रो. वीरभारत तलवार 121

सम्पादकीय

हम सबसे भयावह दौर में हैं

इस देश के जन्मजात वंचितों के नजरिये से यदि आजाद भारत के इतिहास का आंकलन करें तो पाएंगे कि हम निर्विवाद रूप से सबसे भयावह दौर से से गुजर रहे हैं। इस दौर में आजाद भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली सरकारों में से एक, मोदी सरकार जो फैसले ले रहे रही है, वह जन्मजात वंचितों के लिए दुःस्वप्न है। इस दौर में श्रम कानूनों को निरंतर कमजोर किया एवं नियमित मजदूरों की जगह ठेकेदारी प्रथा लागू कर मजदूर वर्ग को अभूतपूर्व शोषण के दलदल में फंसाया जा रहा है। साफ दिख रहा है कि आज भारत की राजनीति पूरी तरह नवउदारवाद के खूनी पंजों में आ चुकी है और देश का शासक वर्ग कार्पोरेट के एजेंट की भूमिका में उतर आया है। जनता का पैसा कार्पोरेट के विकास में लगे और जनता को भान न हो, ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं।'[1] सरकार भारी संख्या में लाभजनक उपक्रमों को निजी हाथों में देने में अभूतपूर्व तत्परता दिखलाने के साथ-साथ बेखौफ होकर सुरक्षा तक से जुड़े उपक्रमों में 100 प्रतिशत एफडीआई लागू कर रही है।

साल में दो करोड़ नौकरियां देने की जगह, अब नौकरी पैदा करने की नसीहत

हर साल दो करोड़ नौकरियां दिलाने का वादा कर सत्ता में आई सरकार ने केंद्र की भर्तियों में 89 प्रतिशत तक की कटौती कर दिया है। बीते मार्च में इसकी पुष्टि करते हुए सरकार की ओर से बताया गया था कि 2013 में 1, 51, 841 नौकरियां दी गयी थीं, जो 2014 में घटकर 1, 26, 261 रह गयीं और 2015 में केवल 15, 877 लोगों की सीधी भर्ती की गई। सरकार बुलेट ट्रेन की नीव रख दी है, किन्तु रेलवे में दो लाख खाली पड़े पद नहीं भर रही है। इस दौर में देश की शान समझी जाने वाली इंडियन एयर लाइन्स और रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में देने की तैयारी शुरू हो चुकी है और सरकारी अस्पतालों, बैंकों, स्कूलों, सार्वजनिक

परिवहन व्यवस्था की हालत सुनियोजित तरीके से पतली की जा रही है ताकि इन क्षेत्रों को निजी हाथों में देने की मांग खुद जनता ही उठाने लगे। इसके लिए सरकार समर्थक बुद्धिजीवी और मीडिया भी माहौल बनाने में जुट गयी है। 'अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक हैं नौकरियां हैं, लेकिन हम रोजगार के मौके कम होते देख रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 के दौरान 15 लाख छीन गयीं। सालाना 2 करोड़ नौकरियों पैदा करने के अपने वादे को अनदेखा करते हुए प्रधानमंत्री ने नौकरियां मांगने की बजाय पैदा करने की नसीहत दे डाली है।'[2]

टॉप की दस प्रतिशत आबादी के पास 81 प्रतिशत धन-संपत्ति

डॉ. आंबेडकर ने 25 नवम्बर, 1949 को राष्ट्र को चेताते हुए कहा था कि हमें जल्द से जल्द आर्थिक और सामाजिक विषमता का खात्मा कर लेना होगा नहीं तो विषमता से पीड़ित जनता गणतंत्र की व्यवस्था को विस्फोटित कर देगी। किन्तु आजाद भारत के शासकों ने बाबा साहेब की उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। 'उसकी अनदेखी पंडित नेहरू, इंदिरा गाँधी, जय प्रकाश नारायण, राजीव गांधी, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इत्यादि राजनीति के सुपर स्टार तक कर गए। बाद में जब नयी सदी में विकास का नया दौर शुरू हुआ, उसके खतरों से निपटने के लिए एक दशक पूर्व देश के अर्थशास्त्रियों और बुद्धिजीवियों ने जो अपील किया, उसकी अनदेखी मोदी की भाजपा सहित दूसरे दल भी करते गए। फलतः पिछले एक दो सालों में विषमता पर देश-विदेश की जितनी भी रिपोर्टें आईं हैं, उनमें पाया गया कि भारत जैसी विषमता दुनिया में कहीं और है ही नहीं। इस मामले में वैश्विक धन-बंटवारे पर क्रेडिट सुइसे की रिपोर्ट काफी चौकाने वाली रही, जिसमें बताया गया था कि सामाजिक आर्थिक न्याय के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद भारत में तेजी से आर्थिक गैर-बराबरी बढ़ी है। 2000 से 2015 के बीच जो कुल राष्ट्रीय धन पैदा हुआ, उसका 81 प्रतिशत टॉप की दस फीसद के पास गया। जाहिर है शेष निचली 90 प्रतिशत आबादी के हिस्से में मात्र 19 प्रतिशत धन आया। उस रिपोर्ट के मुताबिक 19 प्रतिशत धन की मालिक 90 प्रतिशत आबादी में से भी नीचे की 50 प्रतिशत आबादी के पास 4.1 प्रतिशत ही धन आया।'[3] क्रेडिट सुइसे की ही बात को आगे बढ़ाते हुए मार्च, 2017 में प्रकाशित 'मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में बताया गया कि 'मानव विकास के मामले में विश्व के 187 देशों में से 131 वें स्थान पर रहने वाला भारत अरबपतियों

की संख्या के हिसाब से चौथे स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 के दौरान भारत की सर्वाधिक धनी 1 प्रतिशत आबादी के पास 37 प्रतिशत संपत्ति हुआ करती थी जो 2005 में बढ़कर 42 प्रतिशत, 2010 में 48 प्रतिशत, 2012 में 52 प्रतिशत तथा 2016 में 58.5 प्रतिशत तक पहुँच गयी।'[4]

दुसाध के व्यक्तित्व और कृतित्व को सामने लाने की क्यों पड़ी जरुरत!

उपरोक्त तथ्यों के आईने में क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता कि हम सबसे भयावह दौर में वास नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई भी इंकार नहीं कर सकता। इन्कार इस बात से भी नहीं कर सकता कि इससे बहुजन समाज उद्‌भ्रान्त होकर हाँथ-पैर मार रहा है पर, कोई सटीक रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऐसे में हमने बहुत सोच-समझकर देश के जाने माने विचारकों की राय के जरिये 'डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया' के रूप में विख्यात एच. एल. दुसाध के व्यक्तित्व और कृतित्व को सामने लाने का प्रयास किया है। एच. एल. दुसाध के व्यक्तित्व और कृतित्व को सामने लाने का मतलब पाठकों को आम लेखकों की भांति उनके जीवन संघर्ष से नहीं, डाइवर्सिटी नामक एक ऐसे वैचारिक आन्दोलन से रूबरू कराना है, जिसमें देश ही नहीं, मानव जाति की हर बड़ी समस्या का हल है।

यह आरक्षण पर संघर्ष का परिणाम है

बहरहाल उपरोक्त पंक्तियों में जन्मजात वंचितों के लिहाज से जो भयावह तस्वीर उभरी है, उसे आमतौर पर अर्थशास्त्री सरकारों की गलत नीतियों का परिणाम बताकर संतुष्ट हो जाते हैं। पर, क्या सरकारों की गलत नीतियों के चलते ही ऐसा हो गया या इच्छाकृत रूप से ऐसा किया गया! क्या दुसाध के शब्दों में डॉ. आंबेडकर द्वारा लोकतंत्र के ढाँचे के विस्फोटित होने की चेतावनी के बावजूद पंडित नेहरु, जेपी, वाजपेयी इत्यादि से लगाये, 70 सालों में जो नहीं हुआ, वह अब हो रहा है का दावा करने वाले महाशक्तिशाली नरेंद्र मोदी विश्व में सर्वाधिक भीषण रूप में फैली विषमता की समस्या की यूं ही अनदेखी किये जा रहे हैं? क्या नवउदारवादी अर्थनीति की जिस संगठन के लोग यह कहकर वर्षों से शोर मचाते रहे हैं कि 'अब जो स्थितियां और परिस्थितियां बन या बनाई जा रही है, उसके फलस्वरूप देश आर्थिक रूप से विदेशियों का गुलाम बन जायगा, फिर हमें विदेशियों से स्वतंत्रता संग्राम की भांति आर्थिक मुक्ति का संग्राम चलाना पड़ेगा, वैसे संगठन से प्रशिक्षित लोग यूं ही सुरक्षा तक से जुड़े उपक्रमों में 100 प्रतिशत एफडीआई लागू कर रहे

हैं?[5] क्या यूं ही श्रम कानूनों को खत्म तथा भर्तियों में 90 प्रतिशत तक की कटौती करने के साथ-साथ ऐसे हालात बनाये जा रहे हैं जिससे एयर इंडिया, बैंक, रेलवे स्टेशनों सहित तमाम लाभजनक सरकारी उपक्रम, सरकारी अस्पताल, जेल, स्कूल इत्यादि निजी हाथों में चले जायं? क्या यूं ही हजारों साल से शिक्षालयों से दूर धकेले गए बहुजनों को उच्च शिक्षा से पूरी तरह आउट करने के लिए शिक्षा का दैविक अधिकारी वर्ग सर्वशक्ति लगा रहा है?[6] नहीं! इन सवालों का जवाब और लोग चाहे कुछ भी दें, दुसाध का अध्ययन कहता है कि यह सब शक्ति के समस्त स्रोतों (आर्थिक-राजनीतिक- धार्मिक-शैक्षिक इत्यादि) पर 80-85 प्रतिशत कब्जा जमाये परम्परागत विशेषाधिकारयुक्त व सुविधाभोगी तबके को और शक्तिसंपन्न तथा मूलनिवासी बहुजनों को पूरी तरह शक्तिहीन करने की सुपरिकल्पित योजना के तहत किया गया है और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत का इतिहास आरक्षण पर संघर्ष का इतिहास है।'[7]

भारत का इतिहास : आरक्षण पर केन्द्रित संघर्ष का इतिहास

भारत का इतिहास आरक्षण पर संघर्ष का इतिहास है, इस विषय में दुसाध ने बहुत विस्तार से बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का घोषणा पत्र (पृ. 17-43 तक) सहित अन्य कई पुस्तकों और लेखों में लिखा है। उन्होंने इसकी भूमिका बांधते हुए लिखा है-'सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में हर व्यक्ति, समूह और संगठन ने इतिहास से प्रेरणा लेने की कोशिश की है। इस क्रम में उसने मानव के संघर्षों के मूल अंतर्विरोध को समझने की कोशिश किया है, जो देश-काल की परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न बिन्दुओं पर रहा है। लेकिन जो कारण सर्वत्र व्याप्त रहा, वह आर्थिक कारण है। अर्थात दुनिया में सर्वत्र ही मानव-मानव के बीच लड़ाई का कॉमन कारण संपदा-संसाधनों का कब्जा जमाना रहा है। संभवतः इसीलिए दुनिया के महानतम विचारक मार्क्स ने कहा है कि दुनिया (मानव जाति) का इतिहास वर्ग व आर्थिक संघर्ष का इतिहास है। पर, अगर मार्क्स के अनुसार मानव जाति का इतिहास वर्ग व आर्थिक संघर्ष का इतिहास है तो भारत का इतिहास आरक्षण पर संघर्ष का ही इतिहास है। और अगर भारत का इतिहास आरक्षण पर संघर्ष का इतिहास है तो वह मूलतः वर्ण/जातिय संघर्ष का इतिहास है।'[8]

आरक्षण पर संघर्ष के आधुनिक नायक

भारत का इतिहास सिर्फ और आरक्षण पर संघर्ष का इतिहास है, इसकी युक्ति खड़ी

करते हुए दुसाध कहते हैं कि जिस वर्ण-व्यवस्था के द्वारा यह देश सदियों से परिचालित होता रहा है, उसके प्रवर्तकों ने इसकी परिकल्पना चिरस्थाई तौर पर शक्ति के स्रोतों (आर्थिक-राजनीतिक- धार्मिक-शैक्षिक इत्यादि) को पूरी तरह अपनी भावी पीढ़ी के लिए आरक्षित करने को दृष्टिगत रखकर की थी। चूंकि शुद्रातिशूद्र देवासुर संग्राम काल से ही वर्ण-व्यवस्था में शक्ति के स्रोतों से पूरी तरह बहिष्कृत रहे इसलिए वे समय-समय पर इसमें अपनी हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करते रहे। इस क्रम में शक्ति के स्रोतों पर काबिज सुविधा-संपन्न वर्ग से उनका संघर्ष होता रहा। संपदा-संसाधनों के हिस्सेदारी के मसले पर शक्ति-शून्य शुद्रातिशूद्रों और शक्ति-संपन्न सवर्णों के मध्य संघर्ष ही भारत में वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आधुनिक भारत में इस संघर्ष को शिखर पर पहुंचाया ज्योतिबा फुले, शाहूजी महाराज, रामासामी पेरियार और खास तौर से डॉ. आंबेडकर ने। आंबेडकर उत्तरकाल में जिन्होंने इस संघर्ष को खासतौर से आगे बढाया, वे थे बिहार के लेनिन जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा और बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम।'[9]

मंडलोत्तर भारत में ही जुटा हिन्दू साम्राज्यवाद के ध्वंस का सामान

प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के बाद वर्ण-व्यवस्था के जिस अर्थतंत्र पर हिन्दू-साम्राज्यवाद शिखर पर पहुंचा और परवर्ती काल में दो-दो नव साम्राज्यवादियों (मुसलमान और इसाइयों) द्वारा अधीन बनाये जाने के बावजूद अटूट रहा एवं जिसके विरुद्ध आधुनिक युग में सशस्त्र संग्राम प्लासी युद्ध से शुरू हुआ, उस साम्राज्यवाद के ध्वंस का जबरदस्त सामान मंडलोत्तर भारत में ही जुटा। दलितों को वितरणहीनता से निजात दिलाने के दूरगामी लक्ष्य को लेकर कांशीराम ने वर्ण-व्यवस्था में वितरणशून्यता का शिकार बनाई गयी जातियों को संगठित करने व उनकी जाति चेतना का राजनीतिकरण करने का जो प्रक्रिया शुरू किया, उसमें 7 अगस्त, 1990 को मंडल की रपट आने के बाद आश्चर्यजनक रूप से उछाल आ गया। तब कलहरत हजारों वंचित जातियों के मध्य आरक्षण के साझा स्वार्थ के कारण जबरदस्त भाईचारा पैदा हुआ। भाईचारा पैदा होने का मतलब हिन्दू साम्राज्यवाद के सुविधाभोगी वर्ग के खिलाफ तीव्र आक्रोश। सदियों की वंचना की पीड़ा उनमें इस कदर पूंजीभूत हुई कि चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंचना हिन्दू आरक्षण के सुविधाभोगी के लिए दुष्कर हो गया। लेकिन जो आरक्षण वंचितों की एकता का आधार बनकर हिन्दू साम्राज्यवादियों की जमीन दरकना शुरू किया, उसे वे आत्म-दाह, संपदा-दाह से लेकर धर्म, धर्म से लेकर चाणक्य नीति के जरिये खत्म करने की दिशा में काफी हद सफल हो गए।

आरक्षण का वर्गीकरण : बहुजन एकता पर शासक दलों का बड़ा हमला

बहरहाल मंडल उत्तरकाल के ढाई दशकों में सवर्णवादी दलों की नवउदारवादी नीतियों के चलते भारत का परम्परागत विशेषाधिकारयुक्त व सुविधासंपन्न तबका और शक्तिशाली हुआ है। दूसरी ओर निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण की नीतियों ने आरक्षण को लगभग कागजों की शोभा बनाकर दलित, आदिवासी, पिछड़े और इनसे धर्मान्तरित तबकों की हालत बेहद पतली कर दी है। इस काम में गांधीवादी और राष्ट्रवादी, दोनों दलों के प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे को पीछे छोड़ने में होड़ लगाया है। किन्तु दावे के साथ कहा जा सकता है नवउदारवादी नीतियों के जरिये वर्तमान प्रधानमंत्री ने नरसिंह राव, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उनके तीन साल के कार्यकाल का सिंहावलोकन करने पर ऐसा लगता है मानो वह आरक्षित वर्गों से बदला ले रहे हैं। उन्होंने अपनी शातिर चालों से सिर्फ आरक्षण को काफी हद तक खत्म ही नहीं किया है बल्कि, यह जानते हुए भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण भारी मात्रा में आरक्षित पद खाली रह जाते हैं, उन्होंने ओबीसी के आरक्षण में वर्गीकरण के जरिये आरक्षित वर्गों की एकता को शेष करने का खतरनाक चाल चल दिया है। फिलहाल वह ऐसा ओबीसी के आरक्षण में कर रहे हैं। किन्तु निकट भविष्य में ऐसा एससी/एसटी के आरक्षण के साथ नहीं हो सकता, इसके प्रति आश्वस्त होना कठिन है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बहुजन एकता शक्ति के स्रोतों पर सदियों से कब्जा जमाये सुविधाभोगी वर्ग के लिए मंडल उत्तरकाल में आतंक का सबब बन गयी थी, मोदी ने उस पर अभूतपूर्व आघात कर दिया है। ऐसा करने के क्रम में वे आरक्षण के संघर्ष पर केन्द्रित भारतीय इतिहास में सुविधाभोगी वर्ग के महानतम नायक के रूप में उभरे हैं। इस कारण ही आज 'भाजपा संघ के दर्जनों आनुषांगिक संगठनों सहित 90 प्रतिशत सवर्णवादी मीडिया, 90 प्रतिशत पूंजीपतियों और प्रायः 90 प्रतिशत से अधिक साधु-संतों का समर्थन पाकर एक अप्रतिरोध्य दल के रूप में उभर गयी है।'[10]

सारांश में यही कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत से शुरू हुए आरक्षण पर केन्द्रित संघर्ष में शुद्रातिशूद्र वर्ग न सिर्फ निर्णायक रूप से अपनी लड़ाई हारता प्रतीत हो रहा है, बल्कि जो आरक्षण परस्पर कलहरत इस वर्ग को जोड़ता है[11], आरक्षण के वर्गीकरण के जरिये उस एकता को भी छिन्न-भिन्न करने की जमीन तैयार की जा रही है। अगर शासक दल आरक्षित वर्गों में शत्रुता फैलाने के षडयंत्र

सफल हो जाता है, तब भविष्य में बहुजनों की सत्ता कायम होना भी बहुत कठिन हो जायेगा। इसीलिए हमारा मानना है कि हम इस समय सबसे भयावह दौर से गुजर रहे हैं और उससे उबरने में सर्वाधिक कारगर हो सकता है दुसाध का डाइवर्सिटी चिंतन, क्योंकि उन्होंने आज के हालात की कल्पना कर ही लगातार लेखन और चिंतन किया है।

इतिहास के गर्भ से निकला डाइवर्सिटी का मुद्दा

इस विषय में दुसाध ने लिखा है, 'जब मंडलोत्तर भारत में आधुनिक भारत के चाणक्य नरसिंह राव ने 24 जुलाई , 1991 को नयी वैश्विक अर्थनीति(रणनीति)ग्रहण की, तब शुद्रातिशूद्रों के मन में यह आशंका पैदा हुई कि यह सब आरक्षण के खात्मे के लिए किया जा रहा है। ऐसे में उनमें निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कुंडली मारने लगी। धीरे-धीरे कई संगठन निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को लेकर कई सड़कों पर उतरने लगे । और जब राष्ट्रवादी अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आकर अपने गुरु नरसिंह राव को बौना बनाने का लक्षण दिखाने लगे, तब मूलनिवासी शुद्रातिशूद्रों को शतप्रतिशत विश्वास हो गया कि सत्ता पर काबिज हिन्दू आरक्षणवादियों का एकमेव लक्ष्य आंबेडकरी आरक्षण को कागजों तक सिमटाना है। तब निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग शोर में बदलने लगी। सभा-सेमिनारों, पत्र-पत्रिकाओं में यह नयी मांग अधिक से अधिक स्पेस बनाने लगी। और समस्त आर्थिक गतिविधियों को निजी हाथों में देने पर आमादा वाजपेयी जब 31 मार्च, 2003 तक का समय रहते, 31 मार्च, 2001 तक ही 1429 वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के बाद, परम आंबेडकर विरोधी अरुण शौरी को विनिवेश मंत्री बनाकर सरकारी उपक्रमों को औने-पौने दामों में बेचने की दिशा में तेजी से आगे बढे, उन्ही दिनों चंद्रभान प्रसाद और उनके कुछ सहयोगियों के सौजन्य से भारतीय बौद्धिक क्षितिज पर सर्वव्यापी आरक्षण वाली डाइवर्सिटी का उदय हुआ। बाद में उनके ही उद्योग और अब्राहम लिंकन जैसे संवेदनशील हृदय के स्वामी व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सक्रिय सहयोग से 12-13 जनवरी, 2002 को दलित बुद्धजीवियों का महासम्मेलन अनुष्ठित हुआ। दो दिनों के भारी विचार मंथन के बाद उस सम्मलेन से इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों से निबटने और सामाजिक परिवर्तन की धारा को तीव्रतर करने के उद्देश्य से 'डाइवर्सिटी' केन्द्रित 21 सूत्रीय दलित एजेंडा जारी हुआ, जिसे 'भोपाल घोषणापत्र' भी कहते हैं।

भोपाल घोषणा को दलित मुक्ति का चार्टर मानते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने 25 जनवरी, 2002 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसे अपनाने की अपील कर डाली थी। घोषित तौर पर भोपाल घोषणा इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों से निपटने का 21 सूत्रीय एजेंडा था पर, सच तो यह है कि कई हजार वर्ष पूर्व वैदिक मनीषियों ने वर्ण-व्यवस्था (हिन्दू-आरक्षण)के सूत्रों द्वारा मूलनिवासियों के समक्ष जो पहाड़ समान समस्याएं खड़ी की थी, इक्कीसवीं सदी में उसी का मुकम्मल प्रतिकार था, डाइवर्सिटी केन्द्रित दलित एजेंडा। यह आरक्षण के संघर्ष पर केन्द्रित भारत के इतिहास में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का आगाज था।

2002 की जनवरी में भोपाल कांफ्रेंस के बाद डाइवर्सिटी ने राष्ट्र का बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित किया था पर, लोग शंकित थे कि क्या वंचितों को राष्ट्र की प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सेदारी दिलाने वाली डाइवर्सिटी कभी लागू हो पायेगी? किन्तु जब 27 अगस्त, 2002 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकारी आदेश से सप्लायर डाइवर्सिटी लागू की, तब आरक्षण के खात्मे की आशंका से भयाक्रांत ढेरों दलितों में एक नयी उम्मीद का संचार हुआ। फिर तो ढेरों व्यक्ति व संगठन अपने-अपने तरीके से डाइवर्सिटी आन्दोलन को आगे बढाने में जुट गए। नेताओं में जहां डॉ. संजय पासवान ने इस मुद्दे पर पहली बार संसद का ध्यान आकर्षित करने के बाद कई संगोष्ठियां आयोजित किया, वहीं बीएस-4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरके चौधरी ने निजी क्षेत्र में 'आरक्षण-अमेरिका के डाइवर्सिटी पैटर्न पर' को अपनी राजनीतिक पार्टी का एकसूत्रीय एजेंडा बनाकर डाइवर्सिटी के पक्ष में अलख जगाना शुरू किया। भोपाल घोषणा से प्रेरित होकर कई संगठनों ने डाइवर्सिटी केन्द्रित मांगपत्र जारी किया। इस बीच कई डाइवर्सिटी संघर्ष समितियां भी अस्तित्व में आईं, जिनमें दिल्ली डाइवर्सिटी ग्रुप और उत्तर प्रदेश डाइवर्सिटी ग्रुप स्वयं चंद्रभान प्रसाद की देखरख में गठित हुआ।'[12] लेकिन मध्य प्रदेश में सप्लायर डाइवर्सिटी लागू होने के बाद डाइवर्सिटी लागू करवाने को लेकर जो ढेरों संघर्ष समितियां वजूद में आईं, कुछ वर्षों बाद उनके उत्साह में भाटा शुरू हो गया। इसे लेकर जो माहौल बना था, वह गायब होने लगा। इसमें नए सिरे से उत्साह का संचार तब हुआ जब 15 मार्च 2007 को एच. एल. दुसाध ने बहुजन लेखकों को लेकर 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन संगठन'(बीडीएम) की स्थापना किया। इसकी स्थापना का सबब बताते हुए दुसाध जी ने लिखा है-'राज्यों से लेकर केंद्र सरकारों की डाइवर्सिटी के प्रति भयावह अरुचि; अफरमेटिव एक्शन प्लान को कोटे में तब्दील करने में उद्योग

चौम्बरों की भारी अनिच्छा और मौजूदा विकास दर में बहुजनों की नगण्य भागीदारी सहित लगभग आधे दर्जन अन्यान्य कारणों ने हमें भागीदारी दर्शन के महानायक कांशीराम के जन्मदिवस पर बहुजन डाइवर्सिटी की स्थापना के लिए बाध्य किया।'[13]

आर्थिक विषमता के खात्मे के लिए ही वजूद में आया : बीडीएम

वास्तव में आर्थिक में आर्थिक विषमता के खात्मे के लिए ही बीडीएम वजूद में आया। इसका खुलासा करते हुए दुसाध जी ने कहा है, 'चूँकि बीडीएम भी मानता है कि आर्थिक विषमतायें ही वह मर्ज है, जिसके कारण मानव समाज में दूसरी विषमताएं और असह्य वेदनाएं देखी जाती हैं तथा यह भूमंडलीकरण के दौर में भारत में और विकराल रूप धारण करेगी, इसलिए इसका एकमात्र लक्ष्य देश में सदियों से व्याप्त आर्थिक गैर-बराबरी दूर करना है। इसके लिए यह मुख्य रूप से मूलनिवासियों (दलित/आदिवासी-पिछड़े व इनसे धर्मान्तरित) को उनकी संख्यानुपात में शासन-प्रशासन और देश के कारोबार में भागीदारी दिलाने के उपायों पर कार्य करेगा।'[14] ऐसे में आर्थिक विषमता के दूरीकरण के उद्देश्य से बीडीएम मान्यवर कांशीराम के भागीदारी दर्शन और अमेरिका के डाइवर्सिटी सिद्धांत से प्रेरणा लेकर, भारत की सामाजिक विविधता को सामाजिक प्रतिनिधिकरण में रूपायित करने अर्थात विविधतामय भारत के चार सामाजिक समूहों -1 अनुसूचित जाति/जनजाति, (2) पिछड़ा वर्ग, (3) धार्मिक अल्पसंख्यकों और (4) सवर्णों के संख्यानुपात में अवसरों के बंटवारे के लिए राष्ट्र को तैयार करने का अभियान चलाने की घोषणा करता है।'[15]

मानव जाति की बड़ी समस्याएं : विविधता की अनदेखी का परिणाम

आर्थिक विषमता पर दुसाध जी का उपरोक्त चिंतन नयी सदी के शुरूआती दौर का है, जो 2007 में प्रकाशित 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का घोषणापत्र' में नजर आया। लेकिन इस समस्या पर निरंतर चिंतन-मनन करने के बाद परवर्तीकाल में वह आर्थिक के साथ सामाजिक विषमता को एक साथ मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या करार देने लगे। उनका यह संशोधित विचार 2012 में प्रकाशित उनकी रचना 'मानव जाति की बड़ी समस्याएं : विविधता की अनदेखी का परिणाम' में पूरी तरह निखर कर सामने आया। उस पुस्तक में इसी शीर्षक से छपा एक लेख हमने इस पुस्तक में भी डाला है ताकि पाठक मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या के विषय में दुसाध के चिंतन की झलक पा सकें। इस लेख की भूमिका में चरमोत्कर्ष

पर पहुंची मानव सभ्यता को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा है, 'किन्तु तमाम उपलब्धियों के बावजूद दावा नहीं किया जा सकता कि मानव जाति पूरी तरह से समस्यामुक्त हो चुकी है। हम कई तरह के संकटों से जूझ रहे हैं जिसके लिए खासतौर से जिम्मेवार है मानव जाति में विविधताओं को सम्मान देने के पर्याप्त गुणों का अभाव।'[16] मानव जाति के दो बड़े संकटों—'सभ्यताओं के टकराव' और 'ग्लोबल वार्मिंग' के पीछे धार्मिक-सांस्कृतिक तथा जैविक विविधता की अनदेखी की क्रियाशीलता को चिन्हित करते हुए वह 'मानव जाति की बड़ी समस्याएं : विविधता की अनदेखी 'उपशीर्षक में बहुत दावे के साथ कहते हैं-'हंटिंग्टन पंथी सभ्यताओं के टकराव की जितनी भी भयावह तस्वीर पेश करें और पर्यावरणवादी ग्लोबल वार्मिंग की तबाही का जितना भी भयावह खांका खींचें, ये मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या के रूप में चिन्हित नहीं हो सकतीं। हजारों सालों से लेकर आजतक निर्विवाद रूप से आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी ही मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या रही है।'[17]

मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या पर : दुसाध का अनोखा चिंतन

वैसे तो आर्थिक और सामाजिक विषमता को ढेरों विद्वानों ने ही अपने-अपने तरीके से मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या के रूप में चिन्हित किया है। लेकिन इसकी उत्पत्ति का जो वैज्ञानिक सूत्र दुसाध जी ने दिया है, वह सबसे अलग है। उन्होंने साबित किया है—'पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक विषमता की उत्पत्ति समाज में शक्ति के स्रोतों का विभन्न सामाजिक समूहों और उनकी महिलाओं के मध्य असमान बंटवारे से होती रही है। ध्यान देने की बात है कि सदियों से ही मानव समाज जाति, नस्ल, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर कई समूहों में बंटा रहा है। जहां तक शक्ति का सवाल है, समाज में इसके तीन प्रमुख स्रोत हैं-आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। शक्ति के ये स्रोत जिस समूह के हाथों में जितना ही संकेंद्रित रहे, वह उतना ही शक्तिशाली, विपरीत इसके जो जितना ही इनसे दूर व वंचित रहा वह उतना दुर्बल व अशक्त रहा। सदियों से समतामूलक समाज निर्माण के लिए जारी संघर्ष और कुछ नहीं शक्ति के स्रोतों में वंचित तबकों को उनका प्राप्य दिलाना रहा है'।[18] इस समस्या का खात्मा सिर्फ और सिर्फ शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता के प्रतिबिम्बन के जरिये ही क्यों हो सकता है, इस विषय में उनका चिंतन एकदम अनूठा है। उन्होंने कहा है, 'यह सही है कि हजारों वर्षों

से दुनिया के हर देश का शासक-वर्ग ही कानून बना कर शक्ति का वितरण करता रहा है। पर, यदि हम यह जानने की कोशिश करें कि सारी दुनिया के शासक जमातों ने अपनी स्वार्थपरता के तहत कौन सा रास्ता अख्तियार कर सामाजिक और आर्थिक विषमता को जन्म दिया; शक्ति का असमान वितरण किया तो हमें विश्वमय एक विचित्र एकरूपता का दर्शन होता है। हम पाते हैं कि सभी ने ही शक्ति के केन्द्रों में सामाजिक (social) और लैंगिक (gender) विविधता (diversity) का असमान प्रतिबिम्बन करा कर ही मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या को जन्म दिया। अगर हर जगह शक्ति के स्रोतों का बंटवारा विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं की संख्यानुपात में किया गया होता तो क्या दुनिया में आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबर की स्थिति ही पैदा होती?'[19]

शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता के प्रतिबिम्बन के जरिये ही आर्थिक और सामाजिक विषमता से उपजी तमाम समस्यायों का समाधान किया जा सकता है, इसकी उपलब्धि करते हुए ही लोकतांत्रिक रूप से परिपक्व अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया इत्यादि ने अपने-अपने देशों में शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता के प्रतिबिम्बन का अभियान चलाया, जिसके फलस्वरूप वहां के जन्मजात वंचितों - महिलाओं, अश्वेतों, अल्पसंख्यकों- इत्यादि को शक्ति के स्रोतों में वाजिब हिस्सेदारी मिली और वहां शांति और समृद्धि कायम हुई। लेकिन हर बात में विदेशियों की नकल करने वाले भारत के शासक विविधता के मामले में विदेशियों से प्रेरणा नहीं लिए। फलस्वरूप यहाँ हजारों साल के विशेषाधिकारयुक्त व सुविधासंपन्न वर्ग का सदियों से शक्ति के स्रोतों पर 80-85 प्रतिशत कब्जा पूर्ववत है। शक्ति के स्रोतों में शासक दलों के विविधता के प्रतिबिम्बन से परहेज करने के कारण ही आर्थिक और सामाजिक विषमता के जल्द से जल्द खात्मा करने का बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर का 25 नवम्बर, 1949 का आह्वान पूरी तरह व्यर्थ चला और भारत विषमता के भीषणतम दल में फँस गया। ऐसे हालत में ही बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का उदय हुआ। इस पर रोशनी डालते हुए दुसाध ने ने लिखा है -:

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का उदय

'स्वाधीन भारत के शासकों की लोकतंत्र-विरोधी नीतियों के चलते आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी का जो बेइंतहां विस्तार हुआ उसके खात्मे के लिए गाँधीवादी,

माक्सवादी, राष्ट्रवादी, लोहियावादी और आंबेडकरवादी विचारधारा से जुड़े ढेरों राजनीतिक व सामाजिक संगठन 'समतामूलक समाज की स्थापना', 'सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति', सामाजिक विषमता का खात्मा' जैसे आकर्षक नारों के साथ वजूद में आये, पर लक्ष्य से दूर रहे। इसका खास कारण यह रहा कि सामाजिक और आर्थिक विषमता की उत्पति का सुस्पष्ट चित्र उनके पास नहीं था। इसलिए वे टुकड़ों-टुकड़ों में शक्ति अर्जन की लड़ाई लड़ते रहे। कोई भूमि में बंटवारे की तो कोई मजदूरी बढ़वाने की; कोई दलितों के लिए तो कोई पिछडों के लिए; कोई मुसलमानों की तो कोई महिलाओं के हितों की लड़ाई लड़ता रहा। आज की तारीख में कोई पिछडों और मुसलमानों को नौकरियों में तो कोई महिलाओं को राजनीति में आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। इनमें किसी के पास भी ऐसा प्रोग्राम नहीं रहा जिससे मानव-जाति की सबसे बड़ी समस्या का मुकम्मल हल; लोकतंत्र का सुदृढीकरण तथा सभी समुदायों का समान सशक्तिकरण किया जा सके। ऐसी स्थिति में ही 15 मार्च 2007 को हम कुछ अम्बेडकरवादी लेखक-एक्टिविस्टों ने मिलकर 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन' की स्थापना किया। चूंकि मिशन से जुड़े लोगों का यह दृढ विश्वास रहा है कि आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी ही मानव-जाति की सबसे बड़ी समस्या है तथा शक्ति के स्रोतों का लोगों के विभिन्न तबकों और महिलाओं के मध्य असमान बंटवारे से ही सारी दुनिया सहित भारत में भी इसकी उत्पत्ति होती रही है, इसलिए ही हमने शक्ति के सभी स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिम्बन कराने की कार्य योजना बनाया। ऐसे में मिशन के तरफ से निम्न क्षेत्रों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिम्बन कराने अर्थात विविधतामय भारत के चार सामाजिक समूहों-सवर्ण, ओबीसी, एससी/एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों-के स्त्री-पुरुषों की संख्यानुपात में अवसरों के बंटवारे की निम्न दस सूत्रीय कर्मसूची स्थिर किया गया।

1. सेना व न्यायालयों सहित सरकारी और निजीक्षेत्र की सभी स्तर की, सभी प्रकार की नौकरियों;
2. सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा दी जानेवाली सभी वस्तुओं की डीलरशिप;
3. सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा की जानेवाली सभी वस्तुओं की खरीदारी;
4. सड़क-भवन निर्माण इत्यादि के ठेकों, पार्किंग, परिवहन;
5. सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा चलाये जानेवाले छोटे-बड़े स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकि-व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के संचालन, प्रवेश व अध्यापन;

6. सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा अपनी नीतियों, उत्पादित वस्तुओं इत्यादि के विज्ञापन के मद में खर्च की जानेवाली धनराशि;
7. देश-विदेश की संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) को दी जानेवाली धनराशि;
8. प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मिडिया एवं फिल्म-टीवी के सभी प्रभागों;
9. रेल-राष्ट्रीय मार्गों की खाली पड़ी भूमि सहित तमाम सरकारी और मठों की खाली पड़ी जमीन व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए अस्पृश्य-आदिवासियों के मध्य वितरित हो एवं पौरोहित्य में लागू हो विविधता;
10. ग्राम-पंचायत, शहरी निकाय, संसद-विधासभा की सीटों; राज्य एवं केन्द्र की कैबिनेट; विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों; विधान परिषद-राज्यसभा; राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के कार्यालयों इत्यादि।[20]

आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे के लिए बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की ओर से जो दस सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया गया है, उसमें शक्ति के समस्त स्रोतों का लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य वाजिब बंटवारे का निर्भूल सूत्र उभर कर आया है। इसके दस सूत्रीय एजेंडे देश में व्याप्त भीषण आर्थिक विषमता और अन्य कई समस्यायों के निराकरण में कितना प्रभावी हो सकते हैं, इसका जायजा प्रस्तुत पुस्तक के पृष्ठ 57-62 तक का अध्ययन करके लिया जा सकता है। इसके अध्ययन के बाद कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि देश हित में इतना बेहतरीन सूत्र अबतक सामने नहीं होगा।

डाइवर्सिटी लागू करवाने के लिए : फ्रांस क्रांति का रूप देना होगा

इन्ही सब कारणों से प्राख्यात लेखक डॉ. विजय कुमार त्रिशरण ने लिखा है, ‘हमें डाइवर्सिटी सिद्धांत लागू करवाने के लिए इस सम्बंधित आन्दोलन को भारत के 1857 और फ्रांस के 1789 राज क्रांति का रूप देना होगा। बी. डी. एम. का घोषणापत्र बहुजन समाज के उत्थान और उद्धार का एक मंत्र संहिता है।’[21] यह सूत्र कैसे लागू होगा इस पर मार्गदर्शन करते हुए बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के घोषणापत्र में दुसाध जी ने लिखा है-:

‘बीडीएम मुख्यतः वर्ण-व्यवस्था के उन वंचितों के मध्य जन जागरण अभियान चलाएगा जो दैविक गुलामी के कारण वीभत्स संतोषबोध का शिकार हैं; जिनमें हिन्दू आरक्षण द्वारा वित्त वासना इस कदर लुप्त कर दी गयी कि उनमें परिवर्तन या प्रगति कि चाह ही मर गयी। वे टाटा-बिड़ला और हेनरी फोर्ड होना तो दूर,

छोटा-मोटा उद्योगपति व्यापारी बनने का सपना तक नहीं देखते। ऐसे दासों में मा. कांशीराम के सौजन्य से शासक बनने की भावना तो पैदा हुई पर, उद्योगपति, मीडिया स्वामी या किसी फिल्म स्टूडियो का मालिक बनने की महत्वाकांक्षा नहीं। वित्त वासना शून्य ऐसे लोगों में बीडीएम एल. जॉनसन जैसा उद्योगपति, विलियम रास्पबेरी जैसा पत्रकार, ओपरा विनफ्रे जैसी टीवी एंकर, डेंजिल वाशिंग्टन, विल स्मिथ, हैलेबेरी, हूपी गोल्डबर्ग, जेनिफर हडसन इत्यादि जैसे फिल्म सितारे बनने की भावना जागृत करने में सर्वशक्ति लगाएगा। ऐसे में जब मूलनिवासियों में परिवर्तन और प्रगति; उद्योगपति, सप्लायर, डीलर, ठेकेदार, पत्रकार, फिल्म एक्टर इत्यादि बनने की चाह पैदा होगी तब वोट की लालच में राजनीतिक पार्टियां डाइवर्सिटी को अपने चुनावी मैनिफेस्टो का केन्द्रीय मुद्दा बनाने को बाध्य होंगी; फिर प्रशस्त होगा डाइवर्सिटी का मार्ग। इसी रास्ते आकार लेना शुरू करेगा गौतम बुद्ध, फुले, शाहूजी, पेरियार, डॉ. आंबेडकर और कांशीराम साहब का भारत से आर्थिक विषमता मिटाने का सपना ।[2] चूंकि बीडीएम के एजेंडे को लागू करवाने के लिए इसकी घोषित स्ट्रेटजी बहुजनों में उद्योग- व्यापार में हिस्सेदारी की महत्वाकांक्षा पैदा करने के जरिये राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्रों में डाइवर्सिटी को शामिल करवाने की रही है, इसलिए इसकी ओर से भूरि-भूरि साहित्य सृजन के साथ-साथ देश के विभिन्न अंचलों, विशेषकर हिंदी पट्टी में समय-समय पर सभा-संगोष्ठियों के आयोजन किया जाता रहा है।'[23] फलतः आमजन में तो उतनी नहीं पर, प्रबुद्ध जनों और बहुजनवादी संगठनों में भागीदारी की कुछ-कुछ चाह पनपी और वे अपने-अपने तरह से उद्योग-व्यापार में भागीदारी की मांग उठाने लगे। आज तो सोशल मीडिया पर यह चाह प्रायः शोर में तब्दील होती दिख है। निश्चय ही दुसाध जी और बीडीएम से जुड़े उनके साथियों द्वारा छेड़े गए डाइवर्सिटी जैसे वैचारिक आन्दोलन की यह बड़ी सफलता है।

बहुजन मूव्हमेंट को गति देने में 50% योगदान अकेले दुसाध का

यह एक सचाई है जो फेसबुक पर बहुजन समाज के मशहूर आर्थिक चिन्तकBrijpaal bharti के इस कमेंट में उभरी है -: 'राजाराम जी मुद्दे पर टिपण्णी करें । दुसाध जी के बारे में राय बनाने से पहले बहुजन मूव्हमेंट को समझें! बहुजन मूव्हमेंट को गति देने में 50 प्रतिशत योगदान अकेले दुसाध जी का है। मंचों से घंटों बोलने वालों के मुंह से भागीदारी की हिमायत करने वाले शब्द मुख्यतः दुसाध के ही होते हैं, चाहे वो इसे न स्वीकारें।'[24] बहरहाल दुसाध और उनके साथी लेखकों के प्रयास से बहुजन समाज के जागरूक लोगों में नौकरियों से आगे बढ़कर उद्योग-व्यापार

में हिस्सेदारी की जो चाहत पैदा हुई, उसका राजनीतिक दलों पर भी कुछ असर पड़ा और उनके घोषणापत्रों में उसकी झलक भी दिखी। ऐसे में कहा जा सकता है कि दुसाध के नेतृत्व में पार्टियों के घोषणापत्रों में डाइवर्सिटी का एजेंडा शामिल करवाने का बीडीएम का प्रयास खूब व्यर्थ नहीं गया।

राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में डाइवर्सिटी

सबसे पहले भाजपा जैसी पार्टी के घोषणापत्र में डाइवर्सिटी का एजेंडा खुलकर सामने आया। लोकसभा चुनाव-2009 के उसके घोषणापत्र के 29 वें पृष्ठ पर लिखा मिला-'भाजपा सामाजिक न्याय तथा सामाजिक समरसता के प्रति प्रतिबद्ध है। पहचान की राजनीति, जो दलितों अन्य पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य वंचित वर्गों को कोई फायदा नहीं पहुचाती का अनुसरण करने बजाय ठोस विकास एवं सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित करेगी। हमारे समाज के दलित, पिछड़े एवं वंचित वर्गों के लिए उद्यमशीलता एवं व्यवसाय के अवसरों को इस तरह बढ़ावा दिया जायेगा ताकि भारत की सामाजिक विविधता पर्याप्त रूप से आर्थिक विविधता में प्रतिबिम्बित हो।'[25] सामाजिक विविधता का आर्थिक विविधता में प्रतिबिम्बन खालिस दुसाध की शब्दावली है। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने 2010 और 2012 में क्रमशः बिहार और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जारी अपने घोषणापत्रों में भी डाइवर्सिटी को जगह दिया। भाजपा की भांति ही 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा की ओर से डाइवर्सिटी की खुली हिमायत हुई थी। उक्त चुनाव में चूंकि उसका घोषणापत्र राजद के साथ संयुक्त रूप से जारी हुआ था इसलिए घोषणापत्र में तो नहीं, किन्तु रेडियो और टीवी पर जितनी बार भी लोजपा को मतदाताओं को संबोधित करने का अवसर मिला, हर बार उसकी ओर से दोहराया गया-'ठेकेदारी, सप्लाई, वितरण, फिल्म, मीडिया आदि धनार्जन के महत्वपूर्ण अंग हैं। सदियों से व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए राज्य सरकार नीतिगत फैसला नहीं कर सकी। धनोपार्जन के सभी स्रोतों और संसाधनों में सभी वर्गों को डाइवर्सिटी के आधार पर संख्यानुपात में समान भागीदारी और हिस्सेदारी की जरुरत है। लोजपा इसका समर्थन करती है।'[26] डाइवर्सिटी को सिर्फ कुछेक पार्टियों के घोषणापत्रों में ही जगह नहीं मिली, कुछ सरकारों ने इसे आंशिक रूप से लागू भी किया। इस सिलसिले में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का महत्वपूर्ण योगदान है। पढ़ें प्रस्तुत पुस्तक में डाइवर्सिटी आन्दोलन का असर उपशीर्षक से छपी पृष्ठ 122 से 124 तक की सामग्री।

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

✓ We champion diverse voices and perspectives
✓ Your support helps amplify underrepresented authors
✓ We provide free access to educational institutions
✓ Building bridges through shared stories
✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:
• Curate diverse book collections
• Support authors from marginalized communities
• Provide free resources to educators
• Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library